सम्पादकीय

सड़े मांस का कारोबार

मरी हुई मुर्गियों और यहां तक कि मरे हुए पशुओं के सड़े मांस कोलकाता महानगर के विभिन्न होटलों और कुछ रेस्तरां में आपूर्ति करनेवाले गिरोह के सक्रिय होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कोलकाता पुलिस ने लगातार छापामारी कर महानगर के विभिन्न भागों में मरी हुई मुर्गियों के सड़े मांस का कारोबार चलने का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को जो तथ्य हाथ लगे हैं उससे महानगर में सड़े मांस के संगठित कारोबार के फैलने की पुष्टि होती है जो काफी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य के लिए यह कितना हानिकारक है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को लेकर महानगरवासियों तथा खास कर जहां सड़े मांस की बिक्री होती थी वहां के आस-पास के लोगों काफी क्षोभ है। कई जगहों पर तो गुस्साए लोग सड़े मांस के कारोबार करनेवाले अपराधियों को मारने-पिटने पर उतारू हो गए लेकिन पुलिस हिरासत में होने के कारण वे सामूहिक पिटाई से बच गए। पुलिस के व्यापक जांच-पड़ताल करने के बाद सड़े मांस का कारोबार महानगर और आस-पास के जिले उत्तर 24 परगना तथा दक्षिण 24 परगना तक फैलने की जानकारी मिली है।

उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के कौशर अली के ठिकाने पर छापामारी कर पुलिस ने 9 फिज से मुर्गी के सड़े मांस जब्त किए हैं। कौशर अली इलाके का करोड़पति व्यवसायी है। वह बाजार दर से 50 रुपये कम दर पर मुर्गी का मांस बिक्री करता था और महानगर के कुछ होटलों में भी आपूर्ति करता था। छापामारी के बाद कौशर अली फरार है। लेकिन पुलिस को सड़े मांस के कारोबार करनेवाले आठ व्यवसायियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हैरतंगेज बात तो यह है कि महानगर के कूड़ा करकट फेंके जानेवाले शहर के बाहरी क्षेत्र भगाड़ से अन्य मरे पशुओं को संग्रहित करने और उसके मांस में विभिन्न तरह के केमिकल मिला कर बेहतर पैकेजिंग कर डिपार्टमेंटल स्टोर और ब्रांडेड सामग्री बिक्री करनेवाले मॉल में आपूर्ति करने के सुराग मिले है। कोलकाता पुलिस सड़े मांस के कारोबार की गहराई तक जाने की कोशिश कर रही है लेकिन रेस्टॉरेंट में बिरयानी और मांसाहारी भोजन करनेवाले लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर है।

निगम को कोर्ट का डंडा

पूरे विश्व की तरह पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी पानी की किल्लत होना आम है। विशेषकर गर्मियों के दिनों में स्थिति इतनी खराब रहती है कि लोगों को मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहाड़ में कुओं का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। बावड़ियों की सुध लेने का समय किसी के पास नहीं है। तालाबों की जगह दुकानें व उद्योग स्थापित हो गए हैं। भू-जल स्तर को बढ़ावा देने के जो भी उपाय बुजुर्गों ने किए थे, उन पर अमल नहीं हो रहा। लोग इनके संरक्षण के लिए सचेत रहें तो शायद पानी के संकट का सामना करने की नौबत न आए। हर कार्य के लिए शासन-प्रशासन की ओर देखने की सोच को अगर विकसित कर लिया जाए और अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए तो समाज से कई समस्याओं से निजात मिलने में मदद मिलेगी। प्रदेश में सभी मंत्रियों व विधायकों के तालाबों के निर्माण के लिए श्रमदान करने का फैसला सराहनीय है बल्कि लोगों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। प्रदेश सरकार की योजना हर पंचायत में एक तालाब बनाने की है ताकि जरूरत के समय इसके पानी का प्रयोग किया जा सके। सरकार की योजना जल साक्षरता अभियान शुरू करने की है, जिसमें लोगों को पानी के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ये ऐसी पहल है, जिनसे गंभीर समस्या के प्रति सरकार की संजीदगी झलकती है। हाल ही में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की द्वारा करवाए सर्वेक्षण में सामने आया है कि प्रदेश के भूजलस्तर में पांच से 35 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि चिंतित करने वाला खुलासा है। समझना होगा कि तालाबों या प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण से भूजलस्तर को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। बारिश के पानी को सहेजकर भी इस दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। जल संरक्षण में पेड़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि इनके कारण जमीन में नमी बरकरार रहती है। असंभव कुछ भी नहीं है बस जरूरत है मजबूत इच्छाशक्ति और उसे धरातल पर उतारने के इरादों की। जब जागो तभी सवेरा की कहावत पर अमल करते हुए लोगों को जल संरक्षण की दिशा में तन-मन से जुटना होगा ताकि भावी पीढ़ियों को पानी के लिए भटकना न पड़े।

हमारे खान-पान की परंपरा है कि चाय-पकौड़े के बाद पान पेश किया जाता है। लेकिन भाजपा के राज में यह शायद रोजगार की परंपरा बन चुकी है

चाय-पकौड़े के बाद पान

भारती सक्सेना

हमारे खान-पान की परंपरा है कि चाय-पकौड़े के बाद पान पेश किया जाता है। लेकिन भाजपा के राज में यह शायद रोजगार की परंपरा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद खुद का प्रचार चायवाला के तौर पर करवाना पसंद करते हैं और मीडिया इसमें उनका भरपूर साथ देता है। चायवाला वाला जुमला इतना प्रचारित कर दिया गया है, मानो चाय का ठेला लगाने वाले किसी व्यक्ति को ही सीधे चुनाव जीतकर देश संभालने दे दिया गया हो। चाय से बात आगे बढ़ी तो पकौड़ों पर जाकर अटक गई। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में बेरोजगारी पर मोदीजी ने कहा कि अगर आपके दफ्तर के बाहर कोई पकौड़ा बेचता है, तो वह रोजगार नहीं है क्या? इस तरह देश में पकौड़ा रोजगार पर चर्चा शुरु हो गई। विपक्षियों ने पकौड़ों का खोमचा लगाकर भाजपा सरकार का सांकेतिक विरोध किया। यह प्रहसन चल रहा था कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में पकौड़ा राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए। अब यह बात भी आई गई हो गई।

चाय-पकौड़े के बाद अब पान की दुकान लगाकर रोजगार हासिल करने का मंत्र त्रिपुरा की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बिप्लव देब ने दिए हैं। उन्होंने नसीहत दी है कि राज्य के युवा सरकारी नौकरियों के लिए नेताओं के पीछे भागने की बजाय पान की दुकान खोल लेते, तो उनका बैंक बैलेंस लाखों में होता। एक सेमिनार में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी के लिए कई वर्षों तक राजनीतिक दलों के पीछे भागते हैं और अपने जीवन के कई अनमोल वर्ष बरबाद कर देते हैं। अगर यही युवा राजनीतिक दलों के पीछे भागने की बजाय पान की दुकान खोल लेते तो अब तक उनके बैंक में 5 लाख रुपये होते।उन्होंने यह समझाइश भी दी कि यह संकीर्ण सोच है कि ग्रेजुएट खेती या पशुपालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनका स्तर गिर जाएगा। बात तो सही है, काम तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन यहां मुद्दा यह नहीं है कि हम किस काम को छोटा या बड़ा मानते हैं, मुद्दा तो यह है कि सरकार रोजगार देने के अपने वादे को पूरा क्यों नहीं करती है? और किसानों या पशुपालकों की दुर्दशा भी किससे छिपी है। भाजपा सरकार में किसान देश भर में कहीं रैलियां निकाल रहे हैं, कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं, और फिर भी उनकी समस्याओं का हल नहीं मिल रहा तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र में एक किसान ने अपने आत्महत्या के पत्र में बाकायदा प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। मवेशियों को पालने वाले भी धर्म के स्वयंभू रक्षकों के आतंक से ग्रसित हैं। मवेशियों को चराने के लिए ले जाना या बेचने के लिए ले जाना उनके लिए जानलेवा बनता जा रहा है। इसके बाद भाजपा किस मुंह से नौजवानों को खेती करने या पशुपालक बनने की सलाह देती है। और अगर यही करना है तो फिर पूरे देश में कृषि और पशुपालन की पढ़ाई के संस्थान ही खोलने चाहिए। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या अन्य तमाम कोर्स बंद ही कर देना चाहिए।

इंजीनियर बनने वाला नौजवान तो अपनी योग्यता के अनुरूप ही नौकरी चाहेगा। पांच-सात साल जी-तोड़ मेहनत, खर्चीली पढ़ाई कोई इसलिए तो नहीं करता कि उसे पकौड़ा बेचने या पान बेचने की नसीहत मिले। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हर दिन 26 युवा बेरोजगारी की हताशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर चिंता जतलाई है। आईएलओ के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.86 करोड़ रहने का अनुमान है। जबकि 2019 में यह संख्या 1.89 करोड़ तक बढ़ सकती है। कहां तो भाजपा ने 2014 की चुनावी घोषणा में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, और कहां उसके शासन में बेरोजगारी डराने वाली स्थिति पर पहुंच चुकी है।

अपनी बात

अतीत में छिपी भविष्य की कड़ी

अनुज कुमार

नई दिल्ली [जगमोहन सिंह राजपूत]। भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके ग्रंथ और ज्ञानार्जन के लिए विकसित गुरुकुल प्रणाली से सामान्य परिचय भी मनुष्य और प्रकृति के बीच के संवेदनशील संबंधों को उजागर ही नहीं करता है, वरन उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी मनुष्य को ही स्पष्ट रूप से सौंपता है। लोग इन संबंधों के महत्व को धीरे-धीरे भूलते गए, प्रकृति का शोषण लगातार बढ़ता गया कि उसकी क्षतिपूर्ति असंभव होती गई। भारत की ज्ञानार्जन परंपरा और उसके प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को विस्तार से वर्णित किया गया था और अपेक्षा तो यही की जा सकती थी कि भारत प्रकृति के दोहन में स्वयं कभी भागीदार नहीं होगा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रगति और विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों की नकल के फेर में पड़कर भारत अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गया। इसे रोकने में वास्तव में भारत को नेतृत्व प्रदान करना था, मगर भौतिकता की चकाचौंध में भारतीयों ने स्वयं भी वही किया जो अन्य लोग कर रहे थे। परिणामस्वरूप आज पूरी दुनिया विनाश के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है।

अब वैश्विक स्तर पर यह माना जा रहा है कि स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले ऐसी शिक्षा को हर व्यक्तिक पहुंचाना होगा जिसके द्वारा हर व्यक्ति को समाज तथा परिवार और स्वयं अपने लिए अनुशासन और मान्यताओं का बोध हो जिससे प्रकृति का शोषण न हो। यह भी जानना है कि वे कौन से मूल्य और कौशल हैं जिनको अपनाकर विकास की प्रक्रिया भी जारी रखी जाए, मगर उसमें आधार सततता बने न कि वह बेलगाम हो जाए और उसकी दिशा विनाश की ओर मुड़ जाए! इस समय शिक्षाविदों, चिंतकों तथा विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के समक्ष ऐसी शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना को साकार रूप देने की आवश्यकता है जो विकास और प्रगति को सततता का सुदृढ़ आधार प्रदान कर सके। इसके लिए प्राचीन भारत के मनीषियों ने जो दर्शन दिया था उसका पुनः अध्ययन तथा चिंतन आवश्यक है। वह आज भी अपना महत्व रखता है। इसे विश्वव्यापी चर्चा में लाने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उन तत्वों के अंतर्निहित महत्व को समझाने का समय आ गया है जिनमें पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं, नदियों-पहाड़ों-जंगलों में देवत्व देखने की बात कही गई थी, प्रकृति के साथ संवेदनात्मक संबंधों की महत्ता को वर्णित किया गया थाइस समय भारत में शिक्षा की नई नीति की उत्सुकता से प्रतीक्षा हो रही है। नई नीति के लागू होने में कितना समय लगेगा यह कहना तो कठिन होगा, मगर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बहुत कुछ नया करने के निर्णय वैश्विक आधार पर लिए गये हैं जिनमें भारत की सजग और सक्रिय भागीदारी है। 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने '2015 के बाद का विकास एजेंडा' स्वीकृत होने के समय संबोधित भी किया था। इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-2030' यानी सतत विकास लक्ष्य-2030 को स्वीकार किया गया। इसमें चौथे लक्ष्य के रूप में शिक्षा को यूं शामिल किया गया था, 'समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।' चौथे क्रम में शिक्षा का आना पहले तीन के रूप में गरीबी की पूर्ण समाप्ति, भूख की समाप्ति तथा खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की मूलभूत आवश्यकता के साथ ही समग्रता में देखा गया था और उसी के अनुरूप वैश्विक समाज को अपनी कार्ययोजनाओं का निर्धारण करने पर सहमति बनी थी। वर्ष 2000 के बाद सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकासशील क्षेत्रों में नामांकन 91 प्रतिशत तक पहुंचा है। साक्षरता दर बढ़ी है और लड़कियों के शिक्षा में आने से भी इसमें भी वृद्धि हुई है।

अपेक्षा तो यही है कि भारत की शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन के लिए बनने वाले कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास शामिल रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा तो 2030 तक सभी लड़कों और लड़कियों को निःशुल्क, अनिवार्य प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना तय हुआ है। इसके लिए स्कूल-पूर्व की शिक्षा की व्यवस्था की उपलब्धता को आवश्यक माना गया है। भारत में निःशुल्क का अर्थ ही धीरे-धीरे बदल गया है। स्कूली शिक्षा में निजी स्कूलों के आने से तथा सरकारी स्कूलों की साख लगातार कम होने के कारण स्थिति लगातार विषम होती जा रही है। मध्यवर्ग के अधिकांश परिवार निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन स्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये आधे से अधिक हो जाएंगे। 2011 तथा 2015 के बीच के केवल चार साल के अंतराल में सरकारी स्कूलों में 1.1 करोड़ नामांकन कम हुए और उसी दौरान निजी स्कूलों में 1.6 करोड़ बढ़े! एक अनुमान के अनुसार निजी स्कूलों मेंमाता-पिता प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा पर अपनी कुल आमदनी का 24 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत खर्च करते हैं। लगभग सभी पालकों को निजी स्कूलों द्वारा लगातार बढ़ते शोषण का सामना करना पड़ रहा है। अनेक राज्य सरकारें इन पर नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की घोषणा करती हैं, मगर उनका पालन करा पाना लगभग असंभव ही पाया गया है। कारण स्पष्ट है- पालकों के पास कोई विकल्प नहीं है, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के कोई सुनियोजित प्रयास सामने नहीं आ रहें हैं। चूंकि स्कूल-पूर्व की शिक्षा का महत्व अब माता-पिता भी अच्छी तरह समझते हैं और उसका सरकारी स्कूलों में उपलब्ध न होना भी उन्हें निजी स्कूलों की और जाने के लिए बाध्य करता है। सरकारी स्कूलों में इसे उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसका सीधा संबंध स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ता है।

आलेख

जय प्रकाश पाण्डेय

भाजपा सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं जिससे जनता को भरमाये। बच्चा जब खूब रोता है और मां के पास उसकी भूख मिटाने कुछ नहीं रहता तो मां बच्चे का अंगूठा उसके मुंह में दे देती है- बच्चा अंगूठा चूसते-चूसते सो जाता है। भाजपा सरकार भी इसी गुंताड़े में लगी है। अब आगे अगले ही साल चुनाव होगें... जनता को भरमाने के लिए भाजपा सरकार नये-नये तरकीब निकाल रही है।

अंगूठा चूसते हुए बच्चा सो जाता है

केन्द्र की भाजपा सरकार के पास अब जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है- आश्वासनों का पिटारा खाली हो चुका। जुमलेबाजी भी जरूरत से ज्यादा हो गई। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई- हां न्यूज चैनल्स में भाजपा के प्रवक्ता अपनी सरकार को पास का प्रमाण पत्र देते रहे। भारतीय लोकतांत्रिक सरकारों के इतिहास में शायद मोदीजी के नेतृत्व वाली यह सरकार एकमात्र ऐसी हो जिस पर 5 साल पूरा होने से पूर्व ही जनता का विश्वास डिग गया है। वैसे अटलजी की सरकार 5 साल से आगे नहीं चल सकी थी, लेकिन अटलजी की सरकार और मोदी जी की सरकार में एक बड़ा फर्क यह है कि अटलजी की सरकार संयोग की सरकार थी वह कोई बड़े-बड़े वायदे करके नहीं आई थी सत्ता में। सत्ता में आने के बाद %शायनिंग इंडिया% की झूठी चमक दिखाने लगी थी। अतः कोई अटलजी की सरकार अन्य कारणों से गई थी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव पूर्व ही ढेरों मनमोहक वायदे किए इतने कि गिनती तक नहीं की जा सकती। अब तो भाजपा अध्यक्ष उन्हें %चुनावी जुमले% कहने लगे हैं। मोदी जी की सरकार को लेकर जनता में घोर निराशा है- न्यूज चैनल्स में सब हरा-हरा दिखाई देता है। लेकिन बात एकदम अलग है। इस सरकार से जनता के बड़े हिस्से का मोह भंग हो गया है- एक कहावत है कि ऊपर की टीमटाम। अंदर की जाने राम...।। वर्तमान भाजपा सरकार पर कहावत एकदम फिट बैठती है।

भाजपा सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं जिससे जनता को भरमाये। बच्चा जब खूब रोता है और मां के पास उसकी भूख मिटाने कुछ नहीं रहता तो मां बच्चे का अंगूठा उसके मुंह में दे देती है- बच्चा अंगूठा चूसते-चूसते सो जाता है। भाजपा सरकार भी इसी गुंताड़े में लगी है। अब आगे अगले ही साल चुनाव होगें... जनता को भरमाने के लिए

करती है तो कभी झूला झुलाने लगती है। घर में एक दाना नहीं है, लेकिन बच्चे को कहती है कि मुन्ना के लिए मीठी खीर बना रही हैं। भाजपा सरकार भी देश की जनता को भरमाती रही है। शुरू के तीन साल तो जनता भरम में पड़ गई। एक मजेदार बात यह कि जब कांग्रेस नीत यूपीए सरकार 2014 में हारी और भाजपा सत्ता में आई तो बिल्ली के भाग से सींका टूटा की तर्ज पर पेट्रोल के दाम कुछ कम हुए लेकिन अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे।

न्यूज चैनल्स पर महंगाई को लेकर चर्चा होती तो भाजपा प्रवक्ता पेट्रोल के दाम कम होने की बात करते- अब नहीं करते क्योंकि पेट्रोल-डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। जब कांग्रेस नीत यूपीए-2 के समय पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते तो भाजपा आसमान सर पर उठा लेती- कांग्रेस सरकार का सांस लेना मुश्किल कर रखा था। अब चुप है। यह भी सोचनीय है कि कांग्रेस व अन्य आ गए हैं। उनकी आवाज बनने वाले संगठन ही शांत है। वे मानकर चल रहे हैं कि यह तो होते रहेगा- 2014 के चुनाव के समय भाजपा नारे लगाती- %नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अबकी बार भाजपा सरकार... !% और जनता इस लुभावने नारे में बह गई।

2014 के चुनाव सभाओं में मोदी जी कहते रहे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। अब रोजगार-नौकरी की क्या-क्या परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। एक नया जुमला दिया कि युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यह नारा समझ से परे है- कैसे बने नौकरी देने वाले हो और सभी नौकरी देने वाले हो जाएं तो नौकरी कौन करेगा- काम कौन करेगा?

सारे तो मालिक हो गए। कामगार तो कोई नहीं। कितना मनगढ़ंत नारा दिया। और नौकरी की बात निकलने पर स्वरोजगार की बात करने लगते हैं। लोग स्वरोजगार कर रहे- कौशल शिक्षा की बात उठाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है अपने देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग पुरुष-महिला तो स्वरोजगार ही लगे हैं। संगठित क्षेत्र में तो 8-10 करोड़ ही लगे होंगे। अपना देश बहुत ही उद्यमी लोगों का देश है। यहां लोग जरा में हरिया जाते हैं। धान का पौधा देखा है- पानी नहीं बरसता तो धान पिरिया जाता है, सूखे पपड़ी पड़े खेत की मिट्टी में हवा से इधर-उधर डोलता है।

किसान दुखी होता है कि अब की अकाल है। लेकिन पानी गिरा कि वहीं धान के पौधे हरिया जाते हैं- हवा के झोंके के साथ प्रसन्न होकर नृत्य-सा करने लगते हैं। किसान की आशा जरा में हरिया जाती है। भारत की जनता भी 2014 में भाजपा के सुनहरे नारों से हरिया गई लेकिन धोखे में आ गई। मोदीजी प्रायः हर चुनाव सभा में कहते कि विदेशों जमा काला धन वापस लाएंगे- हर भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएंगे। पता नहीं और क्या-क्या वायदे किए, जनता अभिभूत होती गई।